

सुबह से शाम

S.S. Media
Group

तक की खबरें

मूल्य - 2₹

* वर्ष: 19 * अंक: 19 * मुंबई, रविवार, 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2026 * संपादक:- एस.के.तिवारी * पेज: 4 Email Id - ssnews2008@gmail.com www.subahsesham.com

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की मान्यता खत्म करने पर भड़के कपिल सिब्बल बोले— देश में विरोध करना भी अपराध बन गया है

संवाददाता
नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल के रूप में मिली मान्यता समाप्त किए जाने के फैसले पर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने केंद्र की मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की है। शनिवार को आयोजित एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया कि देश में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, जहां विरोध करना भी अपराध माना जाने लगा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के संवैधानिक अधिकार की रक्षा करेगा। सिब्बल ने कहा कि लोकतंत्र में नागरिकों को सरकार की नीतियों और फैसलों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार इस अधिकार को सीमित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा- हम आज ऐसी स्थिति में हैं, जहां विरोध करना एक अपराध बन गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो विरोध करने का अधिकार ही अपराध बन गया है, जबकि हमारे देश में विरोध करना एक मौलिक अधिकार है।

जंतर-मंतर की जगह रामलीला मैदान क्यों जाएं प्रदर्शनकारी?
जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन के लिए

निर्धारित स्थल की मान्यता समाप्त करने के फैसले पर सवाल उठाते हुए सिब्बल ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को रामलीला मैदान जाने के लिए कहा जा रहा है, जबकि दशहरा जैसे आयोजनों के दौरान वहां प्रदर्शन करना संभव नहीं होता। उन्होंने सवाल किया कि जब राजधानी में जंतर-मंतर जैसा स्थान पहले से उपलब्ध था, तो उसकी मान्यता समाप्त करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सिब्बल ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध करने के लिए ऐसे स्थान उपलब्ध होने चाहिए, जहां नागरिक अपनी बात प्रभावी ढंग से सरकार और संबंधित संस्थाओं तक पहुंचा सकें।

हिंसा के लिए बाहरी लोगों को ठहराया जिम्मेदार
जंतर-मंतर पर पूर्व में हुए विरोध-प्रदर्शनों का उल्लेख करते हुए सिब्बल ने दावा किया कि हिंसा प्रदर्शनकारियों के कारण नहीं, बल्कि बाहरी लोगों की वजह से हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन स्थल पर बिना किसी स्पष्ट कारण के पथरों से भरा एक ट्रक लाया गया था। उनके अनुसार, कुछ अज्ञात व्यक्तियों और सादे कपड़ों में मौजूद पुलिसकर्मियों ने हिंसा की। सिब्बल ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों को घसीटा गया, उन पर लाठीचार्ज किया गया और महिलाओं

मोदी सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने का आरोप, कहा— विरोध प्रदर्शन मौलिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट से अधिकारों की रक्षा की उम्मीद



के साथ मारपीट हुई। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि विरोध-प्रदर्शनों के दौरान परिवहन सेवाओं पर भी पाबंदियां लगाई गईं। उनके मुताबिक, मेट्रो सेवाएं रोकने और दिल्ली आने वाली ट्रेनों पर प्रतिबंध लगाने जैसे कदमों से प्रदर्शनकारियों की आवाजाही प्रभावित हुई।

विदेशों में लोकतंत्र की बात, देश में विरोध पर पाबंदी क्यों?
सिब्बल ने न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस जैसे शहरों का उदाहरण देते हुए कहा कि दुनिया के कई प्रमुख शहरों में सरकारी संस्थानों के आसपास शांतिपूर्ण विरोध-

संवाददाता
मुंबई। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने राज्यभर में भोजनालयों, फूड आउटलेट्स, रेस्तरां और कैफे के खिलाफ निरीक्षण तेज कर दिए हैं। इसी बीच विभाग के कुछ अधिकारियों पर निरीक्षण के दौरान फूड कारोबारियों से कथित सांटांटा और रिश्वत लेने के आरोप सामने आने के बाद आयुक्त तुकाराम मुंडे ने आंतरिक कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्टों के अनुसार मुंबई, ठाणे और नासिक क्षेत्रों के करीब 20 अधिकारी जांच के दायरे में आ सकते हैं। आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने अचानक निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारियों के साथ मिलीभगत की और नियमानुसार कार्रवाई नहीं की। इन आरोपों की विभागीय स्तर पर जांच की जा रही है।

मालेगांव सुपारी मामले में पांच अधिकारी निलंबित
नासिक डिवीजन से जुड़े मालेगांव सुपारी मामले में कथित अनियमितताओं के चलते पांच खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निलंबित किया गया है। निलंबित अधिकारियों में अविनाश दामाडे, अमित रास्कर, गोपाल कसार, योगेश देशमुख और सुवर्णा महाजन शामिल हैं। बताया गया है कि यह कार्रवाई 15 अक्टूबर को की गई। उन्होंने स्थिति की तुलना 'प्रेसर कुकर' से करते हुए इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। **(शेष पेज 2 पर)**

विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें
अगर आप अपने विशेष अवसरों को खास बनाना चाहते हैं या महत्वपूर्ण सूचनाओं को व्यापक जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, तो साप्ताहिक 'सुबह से शाम तक की खबरें' आपके लिए सही मंच है। चाहे जन्मदिन की बधाई हो, शादी की सालगिरह, गुमशुदगी की सूचना, कानूनीनोटिस या कोई अन्य व्यक्तिगत और व्यावसायिक विज्ञापन, हम आपके संदेश को सही तरीके से पहुंचाने में मदद करेंगे। आपके विज्ञापन से समाचार पत्र को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, जो इसे और बेहतर सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगी।
ईमेल: Email Id - ssnews2008@gmail.com
या वाट्सएप नं. 8898330400

महाराष्ट्र FDA में बड़ी कार्रवाई की तैयारी मुंबई, ठाणे व नासिक के करीब 20 अधिकारी जांच के दायरे में

मालेगांव सुपारी मामले में पांच अधिकारी निलंबित, जब्त स्टॉक नष्ट करने की प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप



10 करोड़ रुपये की सुपारी हुई थी जब्त
मालेगांव में 11 फरवरी 2024 को FDA अधिकारियों ने 3,605 बोरियों में रखी 252.328 मीट्रिक टन सुपारी जब्त की थी। जब्त स्टॉक की कीमत करीब 10 करोड़ रुपये बताई गई थी। प्रयोगशाला जांच में सुपारी को मानव उपभोग के लिए असुरक्षित पाए जाने के बाद अदालत ने इसे नष्ट करने का आदेश दिया था। बाद में इस प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे कि क्या पूरा स्टॉक वास्तव में नष्ट किया गया था या रिकॉर्ड में ही नष्ट दिखाया गया।

रिपोर्टों में दावा किया गया है कि सुपारी को नष्ट करने के लिए एक ही दिन में करीब 11 ट्रकों का इस्तेमाल दिखाया गया था। वाहनों, गवाहों और नष्ट किए गए स्टॉक से संबंधित दस्तावेजों में कथित विसंगतियां सामने आने के बाद मामले की जांच तेज हुई। FDA प्रशासन अब जब्त खाद्य पदार्थों के प्रबंधन, नष्ट करने की प्रक्रिया, दस्तावेजी रिकॉर्ड और अधिकारियों की जवाबदेही में इस प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे कि क्या पूरा स्टॉक वास्तव में नष्ट किया गया था या रिकॉर्ड में ही नष्ट दिखाया गया।

मुंबई में फुटपाथों पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिडे ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

संवाददाता
मुंबई। मुंबई में फुटपाथों पर बढ़ते अतिक्रमण और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ बृहमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने कार्रवाई तेज कर दी है। शनिवार को महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि फुटपाथ केवल पैदल यात्रियों की सुरक्षित और सुविधाजनक आवाजाही के लिए हैं। इन पर दुकानें, स्टॉल लगाने अथवा सामान रखकर रास्ता बाधित करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रखी जाए। आयुक्त अश्विनी भिडे ने वली स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में आयोजित बीएमसी के विभिन्न विभागों की मासिक समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। बैठक में फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने, अवैध विज्ञापन सामग्री के खिलाफ कार्रवाई, वायु प्रदूषण नियंत्रण और महानगरपालिका की प्रशासनिक व्यवस्था को डिजिटल बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की गई।

26 वाडों में 399 फुटपाथों से हटाया गया अतिक्रमण
आयुक्त भिडे ने बताया कि बीएमसी के 'पैदल यात्री पहले' (Pedestrian First) अभियान के प्रथम चरण में मुंबई

के सभी 26 प्रशासनिक विभागों के अंतर्गत 399 फुटपाथों से अतिक्रमण हटाया गया है। महानगरपालिका के अनुसार, इस अभियान के तहत लगभग 500 किलोमीटर लंबाई के सड़क मार्गों को पैदल यात्रियों की आवाजाही के लिए बाधमुक्त किया गया है। अब तक कुल 2,803 अतिक्रमणों और फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई मुख्य रूप से अस्पतालों, स्कूलों, महाविद्यालयों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों के आसपास की गई है, ताकि पैदल यात्रियों, विद्यार्थियों, मरीजों और आम नागरिकों को आवागमन में परेशानी न हो। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई केवल एक बार तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। फुटपाथों पर दोबारा कब्जा करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए।

मुंबई से 52,448 अवैध बैनर, प्लेक्स और पोस्टर हटाए
मुंबई में सार्वजनिक स्थानों पर अवैध विज्ञापन सामग्री लगाने वालों के खिलाफ भी बीएमसी ने व्यापक अभियान चलाया है। महानगर पालिका की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में मुंबई के विभिन्न हिस्सों से कुल 52,448

‘पैदल यात्री पहले’ अभियान के तहत 399 फुटपाथों से हटाए गए अतिक्रमण, 2,803 फेरीवालों और अवैध कब्जों पर कार्रवाई; 52,448 अवैध बैनर-पोस्टर भी हटाए गए



बैनर, प्लेक्स और पोस्टर हटाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 8 से 16 अक्टूबर 2026 के बीच चलाए गए नौ दिवसीय विशेष अभियान में पूरे मुंबई महानगर से 3,537 अनधिकृत विज्ञापन सामग्री जब्त की गई। आयुक्त अश्विनी भिडे ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत विज्ञापन लगाने से शहर की सुंदरता प्रभावित होती है और नियमों का उल्लंघन होता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अवैध विज्ञापन फलक लगाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने और विशेष अभियान लगातार जारी रखने के निर्देश दिए।

वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की भी समीक्षा
बैठक में मुंबई की वायु गुणवत्ता और बढ़ते

सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर सालभर रोक, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोहराया आदेश

संवाददाता
मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में सार्वजनिक सड़कों और रास्तों पर पटाखे फोड़ने पर सालभर लागू प्रतिबंध को दोहराते हुए कहा है कि बेरोकटोक जश्न शहरी इलाकों को “जहरीले गैस चैंबर” में बदल रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उत्सव मनाने का अधिकार नागरिकों के स्वास्थ्य और स्वच्छ हवा के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकता। जस्टिस गिरिश कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई और कल्याण-डोंबिवली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि मानसून के बाद प्रदूषण का स्तर पहले से ही गंभीर रहता है और पटाखों का धुआं स्थिति को और खराब कर सकता है। पीठ ने कहा कि औद्योगिकरण, निर्माण कार्य, बेकरी और छोटी विनिर्माण इकाइयों सहित कई स्रोतों से प्रदूषण फैल रहा है। ऐसे में पटाखों से निकलने वाला अतिरिक्त धुआं नागरिकों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकता है।

साफ हवा भी जीवन के अधिकार का हिस्सा
अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लेख करते हुए कहा कि स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का



अधिकार जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति अपने उत्सव के नाम पर दूसरे नागरिकों को इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि जश्न मनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करते समय हजारों नागरिकों के स्वास्थ्य और संवैधानिक अधिकारों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।

राज्य ने पूर्ण प्रतिबंध का किया विरोध
राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल मिलिंद साठे ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध का विरोध करते हुए कहा कि मौजूदा कानूनों

और नियमों के जरिए इनके इस्तेमाल को नियंत्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बड़ी आबादी वाले शहर में हर व्यक्ति की गतिविधि पर निगरानी रखना प्रशासन के लिए व्यावहारिक रूप से कठिन है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि 22 सितंबर 2026 को जारी उसके पहले के निर्देश पूरे वर्ष आने वाले त्योहारों और सार्वजनिक आयोजनों पर लागू रहेंगे। अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अदालतों के आसपास घोषित साइलेंट जोन में भी नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। **(शेष पेज 2 पर)**

शिक्षा से केवल पढ़े-लिखे नहीं, अधिकार और कर्तव्य समझने वाले जिम्मेदार नागरिक तैयार हों : मुख्यमंत्री फडणवीस

संवाददाता
मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल शिक्षित व्यक्ति तैयार करना नहीं, बल्कि ऐसा नागरिक बनाना होना चाहिए, जो अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझे, समाज के प्रति संवेदनशील हो और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। शिक्षा के माध्यम से समाज के प्रति समर्पित और नैतिक मूल्यों का पालन करने वाले नागरिक तैयार होंगे, तभी देश की प्रगति को वास्तविक गति मिलेगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री फडणवीस मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) की ओर से शुरू की गई 'सुजाण नागरिक-सक्षम भारत (स्मार्ट नागरिक)' शैक्षणिक पहल के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। दादर पश्चिम स्थित मुंबई पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री फडणवीस और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई ने नागरिक शास्त्र एवं संवैधानिक मूल्यों पर

आधारित 'स्मार्ट नागरिक' तथा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के जीवन पर आधारित 'विद्यार्थी प्रेरणा' पुस्तिकाओं का विमोचन किया। इस अवसर पर मुंबई की महापौर रिंतु तावडे, उपमहापौर संजय घाडी, विधायक अमित साटम, महेश सावंत, कालिदास कोलंबकर, शिक्षा समिति की अध्यक्ष राजश्री शिरवडकर, बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिडे सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित थे।

संविधान के अधिकारों के साथ कर्तव्यों का पालन भी जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के विद्यार्थियों को विभिन्न संचार माध्यमों से दुनिया भर की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो रही है। इससे एक जागरूक और प्रतिभाशाली पीढ़ी तैयार हो रही है, लेकिन विद्यार्थियों में सामाजिक जिम्मेदारी और कर्तव्य की भावना विकसित करना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समाज द्वारा विकसित व्यवस्थाओं के कारण ही

बीएमसी की 'स्मार्ट नागरिक' शैक्षणिक पहल का शुभारंभ, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई ने विद्यार्थियों से किया संवाद, जनवरी 2027 में होगी 'विद्यार्थी प्रेरणा' पुस्तक पर आधारित परीक्षा

व्यक्ति को शिक्षा और अपने व्यक्तित्व के विकास के अवसर मिलते हैं। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को यह समझना चाहिए कि समाज के प्रति उसकी भी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा देश को दिया गया संविधान भारत की प्रगति का महत्वपूर्ण आधार है। संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि उसके सिद्धांतों को जीवन में उतारना आवश्यक है। न्याय, समानता और समान अवसर जैसे संवैधानिक मूल्य विविध भाषाओं, जातियों, धर्मों और संस्कृतियों वाले भारत को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकों को संविधान से प्राप्त अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों की भी जानकारी होनी चाहिए। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और

मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई के न्यायिक योगदान की सराहना करते हुए कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त किया।

बचपन से ही विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्य विकसित हों:
भूषण गवई
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई ने कहा कि भारतीय संविधान ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संविधान की प्रस्तावना में शामिल न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के मूल्यों को बच्चों के मन में कम उम्र से ही विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अपने अधिकारों के साथ दूसरों की स्वतंत्रता और अधिकारों का भी सम्मान समझना चाहिए। 'स्मार्ट नागरिक' और 'विद्यार्थी प्रेरणा' जैसी पहल विद्यार्थियों में संवैधानिक समझ, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहायक होंगी।



बाबासाहेब आंबेडकर के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने बीएमसी की ओर से 50 मेधावी विद्यार्थियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) विषयों के अध्ययन के लिए सिंगापूर भेजने की योजना की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि आर्थिक परिस्थितियों के कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अवसरों से वंचित नहीं रहना चाहिए। मुंबई की महापौर रिंतु तावडे ने कहा कि महानगरपालिका के शिक्षकों द्वारा तैयार 'स्मार्ट नागरिक' और 'विद्यार्थी प्रेरणा' पुस्तिकाएं विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होंगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अर्थ केवल परीक्षा

उत्तीर्ण करना या डिग्री हासिल करना नहीं है, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने और जिम्मेदारी के साथ जीवन जीने की क्षमता विकसित करना भी है। महापौर ने बताया कि विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण, पानी और बिजली की बचत, सामाजिक समानता तथा सार्वजनिक संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग के बारे में भी शिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 'विद्यार्थी प्रेरणा' पुस्तक पर आधारित मराठी भाषा में परीक्षा जनवरी 2027 में आयोजित करने की योजना है। परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को 14 अप्रैल 2027 को डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की जयंती के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा।

संपादकीय

महंगाई की आग में झुलस रही जनता!

देश में बढ़ती महंगाई एक बार फिर आम आदमी की सबसे बड़ी आर्थिक चिंताओं में शामिल हो गई है। रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर शिक्षा, परिवहन, आवास और घरेलू खर्च तक बढ़ती कीमतों का असर परिवारों के बजट पर पड़ रहा है। सितंबर 2026 में खुदरा महंगाई दर बढ़ने की खबरों ने इस चिंता को और गहरा किया है। महंगाई का सबसे अधिक असर उन परिवारों पर पड़ता है जिनकी आमदनी सीमित है और जिनके लिए हर महीने आवश्यक खर्च पूरे करना ही बड़ी चुनौती है। महंगाई के सरकारी आंकड़े अर्थव्यवस्था की स्थिति समझने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सामान्य नागरिक के लिए इसका वास्तविक अर्थ बाजार में दिखाई देता है। जब आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, दाल, दूध और खाद्य तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं, तो परिवार का पूरा बजट प्रभावित होता है। आमदनी में उसी अनुपात में बढ़ोतरी नहीं होने पर लोगों को दूसरी जरूरतों में कटौती करनी पड़ती है। सबसे अधिक कठिनाई दिहाड़ी मजदूरों, छोटे कर्मचारियों, रिक्शा चालकों, किसानों और अर्धगठित क्षेत्र के कामगारों को होती है। खाद्य पदार्थों की महंगाई विशेष रूप से चिंताजनक है। सब्जियों और अन्य कृषि उत्पादों की कीमतें मौसम, उत्पादन, परिवहन, भंडारण और बाजार में आपूर्ति के आधार पर बदलती हैं। कई बार बिचौलियों की भूमिका और वितरण व्यवस्था की कमजोरियाँ भी कीमतों पर दबाव बढ़ाती हैं। ऐसे में केवल बाजार की परिस्थितियों का हवाला देकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकती। आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति, जमाखोरी पर निगरानी और वितरण व्यवस्था को मजबूत करना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। महंगाई का असर केवल रसोई तक सीमित नहीं रहता। बच्चों की पढ़ाई, स्कूल की फीस, आवागमन, चिकित्सा और घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ने से मध्यमवर्गीय परिवारों की बचत प्रभावित होती है। जिन परिवारों ने मकान, वाहन या शिक्षा के लिए ऋण लिया है, उनके लिए ब्याज दरों में बदलाव अतिरिक्त आर्थिक दबाव पैदा कर सकता है। हालांकि ऋण की किस्तों पर वास्तविक प्रभाव संबंधित बैंक की ब्याज दर और ऋण की शर्तों पर निर्भर करता है।

सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2026 में खुदरा महंगाई दर 5.54 प्रतिशत रही, जबकि खाद्य महंगाई 7.74 प्रतिशत तक पहुंच गई। ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा महंगाई 6.08 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 4.88 प्रतिशत दर्ज हुई। खाद्य महंगाई ग्रामीण क्षेत्रों में 8.06 प्रतिशत और शहरों में 7.18 प्रतिशत रही। ये आंकड़े बताते हैं कि महंगाई का दबाव विशेष रूप से ग्रामीण परिवारों और खाद्य पदार्थों पर अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक का महंगाई लक्ष्य चार प्रतिशत है, जिसके आसपास दो प्रतिशत ऊपर या नीचे की सहनशीलता सीमा निर्धारित है। सितंबर की 5.54 प्रतिशत दर इस ऊपरी सीमा के भीतर है, लेकिन लक्ष्य से काफी अधिक है। इसी बीच रिजर्व बैंक ने नए दो दर में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर उसे 5.50 प्रतिशत कर दिया है। महंगाई नियंत्रित करने के लिए ब्याज दर बढ़ाने का निर्णय महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन इससे नए कर्ज महंगे होने और कुछ मौजूदा ऋणों की किस्तें बढ़ने की आशंका भी रहती है। महंगाई से निपटने के लिए केवल ब्याज दरों में बदलाव पर्याप्त नहीं है। सरकार को कृषि उत्पादों की आपूर्ति व्यवस्था मजबूत करने, भंडारण सुविधाएं बढ़ाने और परिवहन लागत कम करने पर विशेष ध्यान देना होगा। मंडियों से खुदरा बाजार तक कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी की निगरानी भी जरूरी है। जहां जमाखोरी या कृत्रिम कमी के प्रमाण मिलें, वहां कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं उचित कीमत पर उपलब्ध हों, इसके बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। भारत के दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की महत्वाकांक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन आर्थिक विकास का वास्तविक लाभ तभी माना जाएगा जब सामान्य परिवारों की क्रयशक्ति भी मजबूत हो। सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी के साथ रोजगार, वास्तविक आय, बचत और जीवनयापन की लागत पर भी बराबर ध्यान देना होगा। आर्थिक प्रगति का आकलन केवल बड़े आंकड़ों से नहीं, बल्कि आम नागरिक के जीवन में आए सुधार से भी होना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को महंगाई नियंत्रण के लिए समन्वित प्रयास करने होंगे। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, बाजार की नियमित निगरानी, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था और कमजोर आय वर्ग को लक्षित राहत जैसे उपायों को प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही कृषि उत्पादन और आपूर्ति शृंखला में दीर्घकालीन सुधार किए बिना खाद्य महंगाई का स्थायी समाधान कठिन रहेगा। महंगाई केवल आर्थिक आंकड़ा नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों की रोजमर्रा की चिंता है। जब रसोई का खर्च बढ़ता है, बच्चों की शिक्षा महंगी होती है और परिवार की बचत घटती है, तब आर्थिक विकास के बड़े दावे आम नागरिक को पर्याप्त राहत नहीं दे पाते। सरकार और रिजर्व बैंक के सामने चुनौती महंगाई नियंत्रित करने के साथ आर्थिक गतिविधियों और रोजगार को भी बनाए रखने की है। वास्तविक जनकल्याण तभी संभव है जब बढ़ती कीमतों पर प्रभावी नियंत्रण हो और आम आदमी की आय तथा क्रयशक्ति में सुधार आए।

दृष्टिकोण: भय बिनु होय न प्रीत गुसाईं

डॉ. सुधाकर आशावादी

समाज के बदलते चरित्र और मानवीय रिश्तों में बढ़ती अमानुषिकता ने जनमानस को यह विचारने हेतु विवश कर दिया है, कि विश्वास पर टिके रिश्तों के क़त्ल को किस प्रकार से रोका जाए। विगत कुछ वर्षों से पति पत्नी और वो के चलते जिस प्रकार के वीभत्स हत्याकांडों को अंजाम दिया गया है, उससे लगता है कि समाज में वैवाहिक संबंधों में दरार आ गई है, रिश्तों की गमाहट कम हुई है तथा रिश्तों की मर्यादा तार तार हुई है। मेरठ में विगत वर्ष सौरभ राजपूत हत्याकांड में जिस प्रकार की बर्बरता बरती गई तथा मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने जिस प्रकार से सौरभ के जघन्य अपराधों को किस प्रकार से रोका जाए? समाजशास्त्रियों व मनोवैज्ञानिकों के लिए भी समाज में आ रहे इस बदलाव से उत्पन्न होने वाली स्थिति से जुड़े अनेक प्रसंग बड़ी चुनौती के रूप में खड़े थे। इसी बीच सौरभ राजपूत हत्याकांड में मेरठ न्यायालय द्वारा पारित्यजन्य साक्ष्यों के आधार पर मुस्कान व साहिल को मौत की



सजा दिए जाने से अवैध संबंधों के चलते हत्या जैसे वीभत्स अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों में ख़ौफ़ उत्पन्न होना अपेक्षित है। य़ूँ तो मौत की सजा दिए जाने पर कुछ मानवतावादी विचारकों में लंबे समय से बहस छिड़ी है, किंतु भय बिनु होय न प्रीत गुसाईं की अवधारणा यही है कि हिंसात्मक कृत्यों का निदान विनम्रता से संभव नहीं होता। यदि निश्चित प्रक्रिया से अपराधियों को फाँसी की सजा सुनाए जाने के उपरांत शीघ्र फाँसी पर चढ़ा दिया जाता है, तब निस्संदेह यह बड़ी नजीर बनेगी तथा उन अपराधियों के लिए कड़ा संदेश होगा, जो न्याय व्यवस्था को बौना समझते हुए बेखौफ़ होकर अपराधों को अंजाम देते हैं। क्रूरता की पराकाष्ठा से जनि्त नृशंस हत्याओं को अंजाम देने वाले दरिदों को कितना कठोर दंड मिलना चाहिए, कितना नहीं, इस पर व्यापक चर्चा करके जैसे को तैसा जैसा उदाहरण प्रस्तुत करना ही चाहिए? अब समय आ गया है कि जब जघन्य अपराधों को अंजाम देने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने में किसी प्रकार की भी कमी न छोड़ी जाए। यदि उम्र कैद की जगह अपराध की वीभत्सता को दृष्टिगत रखते हुए फाँसी की सजा दी जाए तो अपराधों की बाढ़ में कमी अवश्य ही आएगी।

पेज 1 का शेष

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की...

संविधान के अनुच्छेद 19 का दिया हवाला

वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लेख करते हुए कहा कि नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार प्राप्त है। हालांकि, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था जैसे आधारों पर कानून के अनुसार उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि जंतर-मंतर पर पहले भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए हैं और 10 अक्टूबर को प्रस्तावित ‘जंतर-मंतर 2.0’ प्रदर्शन भी शांतिपूर्ण रहता। सिब्बल ने राहुल गांधी और विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन के सहयोगियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट की ओर निकाले गए मार्च का उल्लेख करते हुए कहा कि वह प्रदर्शन भी बिना हिंसा के संपन्न हुआ था। उन्होंने सवाल किया कि विरोध करने वाले युवाओं के साथ अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों से सरकार को किस प्रकार का खतरा हो सकता है।

बेरोजगारी और आर्थिक हालात को लेकर

भी सरकार पर निशाना

सिब्बल ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए दावा किया कि बेरोजगारी, आर्थिक संकट और सार्वजनिक निवेश में कमी के कारण लोगों का सरकार पर भरोसा कमजोर हुआ है। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान की दिशा में कदम उठाने के बजाय विरोध की आवाज को सीमित करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। सिब्बल ने राजनीतिक टिप्पणी करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार जितनी जल्दी सत्ता से हटेगी, उनके अनुसार देश के लिए उतना ही बेहतर होगा। उन्होंने भरोसा जताया कि सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करेगा। फिलहाल जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की मान्यता समाप्त किए जाने

संस्कृति की जड़ों से जुड़ी पथवारी पूजन परम्परा

डॉ. निर्मला शर्मा

भारतीय संस्कृति में जीवन का कोई भी पक्ष लोकआस्था और परंपरा से अछूता नहीं है। पथवारी पूजन ऐसी ही एक आत्मीय लोकपरंपरा है जो हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ती है। राजस्थान में नवरात्र के दिनों में पथवारी पूजन विशेष रूप से होता है। प्रातः स्नान के बाद कन्याएँ व्रत रखकर श्रद्धापूर्वक पथवारी माता की पूजा करती हैं। यह केवल पूजा नहीं, बल्कि बचपन की स्मृतियों, पारिवारिक संस्कारों और लोकगीतों से जुड़ा विश्वास है। बचपन में हम भी इसका नियमित पालन करते थे। तब न संस्कृति के व्यापक अर्थ का ज्ञान था, न यह समझ कि हमारे छोटे-छोटे क्रियाकलाप हमारी विरासत का हिस्सा हैं। हम तो बस बड़ों को देखकर उनका अनुसरण करते थे। बालमन में प्रश्न उठता कि हम पथवारी की पूजा क्यों करते हैं, तो माँ सहजता से कहती-पथवारी हमारे पथ की रक्षा करती हैं। माँ का यह छोट-सा उत्तर पर्याप्त होता था। फिर रास्ते में डर नहीं लगता था। खेत पर जाना हो, कुएँ पर पानी लेने जाना हो, मन में निर्भयता बनी रहती थी। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि लोकपरंपराएँ केवल पूजा-विधियाँ नहीं, मन में विश्वास और मानसिक संबल जगाने का माध्यम हैं। यही हमारी लोकसंस्कृति की विशेषता है कि वह बिना कठिन उपदेशों के जीवन के संस्कार अगली पीढ़ी तक पहुँचा देती है।

लोकआस्था और

मंगलकामना का प्रतीक

पथवारी पूजन बचपन तक सीमित नहीं है। आज भी जब परिवार का कोई सदस्य यात्रा पर निकलता है, तो परिजन प्रातः पथवारी पूजते हैं और मंगलगीत गाते हैं कि पथवारी माता यात्री के मार्ग की बाधाओं से रक्षा करें और यात्रा निर्विघ्न हो। इस परंपरा में देवी के प्रति श्रद्धा



के साथ अपनों के प्रति चिंता और स्नेह भी निहित है। लोक में पथवारी को मार्ग की रक्षक देवी माना जाता है। जीवन भी एक यात्रा है, जहाँ सरल रास्ते भी हैं और कठिन मोड़ भी। ऐसे में अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा हमें धैर्य और आगे बढ़ने का संबल देती है।

पथ का अर्थ जीवन की दिशा

पथवारी शब्द का संबंध पथ यानी रास्ते से है। भारतीय संस्कृति में रास्ता केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन-यात्रा का प्रतीक है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा मार्ग सुरक्षित रहे और हम लक्ष्य से न भटके। नवरात्र के अन्त्योत्तों द्वारा पथवारी पूजन देवी-शक्ति के प्रति श्रद्धा के साथ अपनी लोकपरंपराओं से जुड़ने का अवसर भी है।

तालाब से गमले तक

मुझे आज भी वे दिन याद हैं जब हम प्रातः तालाब पर स्नान करने जाते और वहीं पथवारी पूजन करते थे। तालाब केवल स्नान की जगह नहीं, हमारे दैनिक जीवन और सामुदायिक गतिविधियों का हिस्सा था। समय के साथ गाँवों से शहरों की ओर विस्तार हुआ। शहरों में न वैसे तालाब हैं, न खेतों की पगडंडियाँ। ऐसे में क्या हम परंपरा छोड़ दें? मेरा मानना है कि परंपरा

के फैसले को लेकर उनके आरोपों और आपत्तियों पर केंद्र सरकार का पक्ष इस बयान में सामने नहीं आया है।

मुंबई में फुटपार्थों पर अतिक्रमण...

इस प्रणाली के माध्यम से महानगरपालिका के कार्यालयीन कामकाज और फाइलों की प्रक्रिया को डिजिटल स्वरूप देने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। बैठक में अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगर) डॉ. विपिन शर्मा, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (परियोजना) अभिजीत बांगर, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगर) डॉ. अविनाश ढाकणे, संयुक्त आयुक्त (सतर्कता) डॉ. एम. देवेंद्र सिंह और उपायुक्त (आयुक्त कार्यालय) प्रशांत गायकवाड उपस्थित थे। इसके अलावा सभी संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त और विभिन्न विभागों के प्रमुख भी बैठक में शामिल हुए।

सार्वजनिक सड़कों पर...

शिकायत व्यवस्था और नोडल अधिकारी

नियुक्त करने के निर्देश

हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्थानीय निकायों और पुलिस को निर्देश दिया कि वे एक सप्ताह के भीतर शिकायत दर्ज कराने की प्रभावी व्यवस्था तैयार करें और नोडल अधिकारी नियुक्त करें। इसके साथ ही शोर प्रदूषण की निगरानी के लिए फील्ड अधिकारियों को डेसिबल मीटर उपलब्ध कराने और नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाने को कहा गया है। अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि जनजागरूकता अभियानों में प्रसिद्ध हस्तियों को शामिल किया जा सकता है। पटाखा विक्रेताओं से भी कम शोर और कम प्रदूषण वाले ग्रीन पटाखों को बढ़ावा देने की अपील की गई है। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर 2026 को होगी, जिसमें अदालत अपने निर्देशों के पालन की स्थिति की समीक्षा करेगी।



मेघ राशि: इस सप्ताह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में नए संपर्क लाभदायक साबित होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।

वृषभ राशि: वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक दृष्टि से अनुकूल रह सकता है। लंबे समय से रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। नौकरी में आपके काम की सराहना होगी और पदोन्नति से संबंधित चर्चा आगे बढ़ सकती है। व्यापारियों को नए सौदे से लाभ मिलने के संकेत हैं। परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

मिथुन राशि: इस सप्ताह नई योजनाओं पर काम शुरू करने के अवसर मिलेंगे। नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे लोगों को सकारात्मक सूचना मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी संवाद क्षमता महत्वपूर्ण साबित होगी। कारोबार में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अचानक खर्च सामने आ सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक एकाग्रता रखनी होगी।परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। सप्ताहांत में छोटी यात्रा संभव है।

कर्क राशि: कर्क राशि वालों को इस सप्ताह धैर्य और साहस से काम लेना होगा। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं। सहकर्मियों के साथ मतभेद होने पर बातचीत से समाधान निकालें। व्यापार में बड़ा निवेश करने से पहले अच्छी तरह विचार करें। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी।

सिंह राशि: सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह उपलब्धियों और नए अवसरों से भरा रह सकता है। नौकरी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यक्षमता से प्रभावित होंगे। कारोबार में विस्तार की योजना आगे बढ़ सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। और आय के नए अवसर मिल सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परिवार में उत्साह और प्रसन्नता का वातावरण रहेगा।

कन्या राशि: इस सप्ताह आपकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। नौकरी में लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे। कार्यस्थल पर आपके सुझावों को महत्व मिलेगा। व्यापार में लाभ के अवसर बनेंगे, लेकिन उधार और बड़े लेन-देन में सावधानी रखें। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से प्रसन्नता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा।

तुला राशि: तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। नौकरी में बेहतर अवसर मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयास सफल होंगे। व्यापारियों को नए ग्राहक या बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, हालांकि घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं। परिवार में आपसी समझ बढ़ेगी। **वृश्चिक राशि:** वृश्चिक राशि वालों को इस सप्ताह सौच-समझकर निर्णय लेने होंगे। कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को समय से पहले सार्वजनिक करने से बचें। व्यापार में सप्ताह का उत्तरार्ध लाभदायक रह सकता है। अचानक खर्च से बजट प्रभावित हो सकता है।

धनु राशि: धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह करियर और कारोबार में प्रगति का संकेत दे रहा है। नौकरीपेशा लोगों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण परियोजना मिल सकती है। व्यापार में दूर के संपर्कों से लाभ होगा। काम के सिलसिले में यात्रा संभव है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचें। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा।

मकर राशि: मकर राशि वालों के लिए सप्ताह व्यस्तता और जिम्मेदारियों से भरा रहेगा। नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत की सराहना होगी। कारोबार में पुराना भुगतान मिलने से आर्थिक राहत मिल सकती है। संपत्ति या वाहन खरीदने की योजना पर विचार हो सकता है। परिवार में नए अवसरों पर खर्च बढ़ेगा। **कुंभ राशि:** कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह नए विचारों और योजनाओं को आगे बढ़ाने का रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मक सोच की सराहना होगी। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अवसर मिल सकता है। व्यापार में तकनीक और नई कार्यप्रणाली अपनाने से लाभ होगा। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। परिवार में किसी गलतफहमी का समाधान होगा।

मीन राशि: मीन राशि वालों के लिए सप्ताह सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। लंबे समय से रुका हुआ कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा होने की संभावना है। नौकरी में आपकी मेहनत की सराहना होगी। कारोबार में नया समझौता लाभदायक साबित हो सकता है। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और बचत बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे।

भारतीय जीवन बीमा से संबंधित किसी भी जानकारी या समस्या समाधान हेतु संपर्क करें।

-भारत सिंह

मो. 9967255741

महत्वपूर्ण सूचना

विज्ञापन प्रति के स्वीकृति पूर्व एहतियातन बरती जाने के बावजूद, उसमें अंतर्भूत बाते जांचना संभव नहीं है। ऐसी अंतर्भूत बातों के लिए सुबह से शाम तक की खबरों के अंतर्गत समाचारपत्र या प्रकाशनों में आनेवाली कंपनियाँ, संस्थाए या व्यक्तिगत विज्ञापनों के साथ हुए किसी भी प्रकार के व्यवहार के लिए समाचार पत्र जिम्मेदार नहीं है।



समाधान विरोध और व्यापार में से किसी एक को चुनना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था विकसित करना है जिसमें दोनों के लिए पर्याप्त स्थान हो। प्रशासन को प्रदर्शन के लिए उपयुक्त स्थल उपलब्ध कराने, वैकल्पिक मार्गों की जानकारी समय पर देने और दुकानों तथा सार्वजनिक परिवहन तक पहुँच बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। प्रदर्शन आयोजकों को भी भीड़ प्रबंधन और नागरिकों की सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। यदि कारोबार को नुकसान पहुँचने का दावा किया जाता है, तो उसकी निष्पक्ष जाँच और प्रमाण आधारित आकलन होना

चाहिए। कर्नाट प्लेस का घटनाक्रम हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र केवल विरोध करने की स्वतंत्रता का नाम नहीं, बल्कि दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने की जिम्मेदारी भी है। जिस व्यवस्था में नागरिक अपनी आवाज उठा सकें, व्यापारी अपनी आजीविका चला सकें और प्रशासन कानून का निष्पक्ष पालन करा सके, वही व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करती है। विरोध की आवाज दबाए बिना बाजार की रौनक बचाना और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करना ही इस चुनौती का वास्तविक समाधान है।

कैंसर मरीजों को बड़ी राहत: महात्मा फुले और आयुष्मान भारत योजना में PET-CT जांच शामिल

संवाददाता
मुंबई : कैंसर की सटीक पहचान, बीमारी का चरण निर्धारित करने और इलाज के असर का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण PET-CT स्कैन की महंगी जांच अब महाराष्ट्र में मातृता ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना के तहत उपलब्ध होगी। राज्य सरकार ने इस संघर्ष में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 63 कैंसर उपचार पैकेज में PET-CT को अतिरिक्त निदान प्रक्रिया के रूप में शामिल किया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी शासन निर्णय के अनुसार, चुनिंदा 13 प्रकार के कैंसर उपचारों में PET-CT स्कैन को स्वतंत्र अथवा नियमित प्राथमिक निदान प्रक्रिया के रूप में भी मान्यता दी गई है। इससे जरूरतमंद कैंसर मरीजों पर महंगी जांच का आर्थिक बोझ कम होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश आठवले ने बताया कि PET-CT जांच की अधिक लागत के कारण कई मरीज इसे टाल देते थे, जिससे बीमारी की स्थिति समझने और समय पर उपचार तय करने में देरी होती थी। नागरिकों और योजना से जुड़े अस्पतालों की मांग को देखते हुए एक अध्ययन समिति गठित की गई थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने यह निर्णय लिया है। पहले 44 कैंसर उपचार पैकेज में PET-

तलोजा ड्रग्स मामले में सप्लाई नेटवर्क का ख़ूलासा, दो और आरोपी गिरफ्तार

संवाददाता
नवी मुंबई। तेलोजा में एक नाइजीरियाई नागरिक के पास से 3.57 करोड़ रुपये की ड्रग्स बरामद होने के मामले की जांच में नवी मुंबई पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स सेल (ANC) ने सप्लाई नेटवर्क से जुड़े दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक नाइजीरियाई नागरिक और असम की एक महिला शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान डेस्टिनी अकाचुकु उगोचुकु (34) और पूम बस्नेत (30) के रूप में हुई है। दोनों दिवा-मुंब्रा इलाके में रह रहे थे। पुलिस ने इन्हें 14 अक्टूबर को गिरफ्तार किया। इससे पहले 8 अक्टूबर को तेलोजा से एनी इन्केचुकु डालिंगटन (41) को गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से और उसके घर की तलाशी में 2.497 किलोग्राम मेफेंड्रोन (MD) और 566 ग्राम कोकोन बरामद हुई थी, जिसकी कुल कीमत करीब 3.57 करोड़ रुपये बताई गई है। पुलिस के अनुसार, डालिंगटन 2019 के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से जुड़े एक मामले में सात साल जेल में रह चुका था और 2025 में जमानत पर बाहर आया

विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में वित्तीय क्षेत्र की भूमिका
निर्णायक: राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

संवाददाता

मुंबई। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने कहा कि बैंक और वित्तीय संस्थाएँ केवल कर्ज और वित्तीय सेवाएँ देने वाली संस्थाएँ नहीं हैं, बल्कि वे राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण भागीदार हैं। बचत को संगठित कर, उद्योगों को पूंजी उपलब्ध कराकर और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त देकर वे रोजगार, नवाचार और समावेशी विकास को गति देती हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में वित्तीय क्षेत्र की भूमिका निर्णायक होगी।

शुक्रवार को राज्यपाल वर्मा मुंबई के वल्लो स्थित होटल फोर सीजन में असोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (असोचैम) द्वारा आयोजित बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र की ऋणदाता कंपनियों के लिए 21वाँ वार्षिक परिषद और पुरस्कार समारोह को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन की थीम 'रेजिलिएंस, रिश्चनैशन एंड इंडिया राइज' रखी गई थी। इस अवसर पर असोचैम अध्यक्ष निर्मल के. मिंडा, महासचिव सौरभ सन्याल, बैंकिंग पर राष्ट्रीय परिषद के सह-अध्यक्ष माधव नायर, राज्यपाल के सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, यस बैंक के कार्यकारी निदेशक मनीष जैन सहित नीति निर्माताओं, नियामक संस्थाओं और बैंकिंग-वित्तीय क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राज्यपाल ने कहा कि 2014 के बाद देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रथममंत्री जनधन योजना, आधार आधारित सेवाओं, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और यूपीआई ने वित्तीय सेवाओं की पहुँच और कार्यप्रणाली को बदल दिया है। हालाँकि उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन केवल बैंक खाता खोलने या डिजिटल भुगतान

63 कैंसर उपचार पैकेज में अतिरिक्त जांच की सुविधा, 13 प्रकार के कैंसर में स्वतंत्र निदान प्रक्रिया के रूप में भी मान्यता



CT की सुविधा उपलब्ध थी। नए निर्णय के बाद इसे बढ़ाकर 63 उपचार पैकेज कर दिया गया है। इसके अलावा चिकित्सकीय रूप से उपयोगी पाए गए 13 कैसर उपचारों में इसे नियमित या प्राथमिक जांच के रूप में शामिल किया गया है। सरकार ने PET-CT जांच के लिए दरे भी तक की है। होल बांडी PET-CT के लिए 20,400 रुपये, ब्रेन के लिए 14,650 रुपये, गैलियम-68 के लिए 15,000 रुपये और कांडिड PET-CT के लिए 9,400 रुपये की दर निर्धारित की गई है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए संबंधित विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा जांच की जा सकती है। चिकित्सकीय आवश्यकता प्रमाणित करना आवश्यक होगा। योजना से जुड़े अस्पताल में आवश्यक तकनीकी उपकरण, प्रशिक्षित

स्टाफ और अपना इन-हाउस PET-CT सेक्टर होना भी अनिवार्य किया गया है। जांच से पहले पूर्व स्वीकृति और आवश्यक चिकित्सकीय दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। राज्य स्वास्थ्य आश्वासन सोसायटी की इस निर्णय के प्रभावी क्रिया-यन्त्र के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की TMS 2.0 प्रणाली में आवश्यक बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि इस निर्णय से कैन्सर मरीजों को समय पर और सटीक जांच उपलब्ध होगी, इलाज की योजना बेहतर तरीके से बनाई जा सकेगी और परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा। उन्होंने राज्य सरकार की कैसर के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम बताया।

नाइजीरियाई नागरिक और असम की महिला पकड़ी गई, अब तक तीन गिरफ्तार, 3.57 करोड़ रुपये की ड्रग्स हुई थी जल्द



था। उसको गिरफ्तारी के बाद जांच में अधिकृत सफ़ाई चैन से जुड़े अन्य लोगों के नाम सामने आए। एंटी-नारकोटिक्स सेल के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संदीप निगाड़े के अनुसार, जांच के दौरान इन सफ़ाई एजेंट्स की कड़ियों का पता लगाना था, जिसके आधार पर डेस्टिनी ओगोचुकु और बूनूम बम्बेने की पहचान हुई। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि नाइजीरियाई आरोपी कथित तौर पर ड्रम्स के लोन-केन के साथ अपने बैंक खाते से जुड़े QR कोड के माध्यम से भ्रगतान लेता था। जांच

एजेंसियां अब वित्तीय लेन-देन की कड़ियों को खंगाल रही हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि भुगतान किस-किस व्यक्ति से आया और नेटवर्क में और कौन शामिल हो सकता है। दोनों आरोपियों को आगे की जांच के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इनकी गिरफ्तारी के साथ मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या तीन हो गई है। पुलिस अब ड्रग्स के स्रोत, उनकी सप्लाई करने वाले लोगों तक की जानी थी और इस नेटवर्क में अन्य व्यक्ति की भी भूमिका की जांच कर रही है।

असोचैम की 21वीं वार्षिक बैठक एवं वित्तीय सम्मेलन में बोले- एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला समूह और बुनियादी ढांचे को समय पर वित्त जरूरी



निक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि गरीब परिवारों, ग्रामीण नागरिकों और छोटे उद्यमियों को सस्ता कर्ज, बीमा, पेंशन और अन्य वित्तीय सेवाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए। राज्यपाल ने त्रिपुरा के वित्त मंत्री के रूप में अपने अनुभव का उल्लेख करते हुए कहा कि शुरुआत में बैंक महिला स्वयं सहायता समूहों को कर्ज देने में हिचकते थे। बाद में यह समझे आया कि इन समूहों की ऋण अदायगी अनुशासित थी और एनपीए बहुत कम था। उन्होंने वित्तीय संस्थाओं से महिलाओं की आर्थिक क्षमता को गंभीरता से पहचानने का आह्वान किया। एमएसएमई क्षेत्र का उल्लेख करते हुए एमएन ने कहा कि कृषि, लघु और मध्यम उद्योग रोजगार, रोजगार, लघु और मध्यम उद्योग और निर्यात में अहम योग्यताएं देते हैं, लेकिन कई इकाइयों को समय पर और कफायती कर्ज नहीं मिल पाता। उन्होंने बैंकों, एनबीएफसी और अन्य वित्तीय संस्थाओं से कृषि, लॉजिस्टिक्स, अक्षय ऊर्जा, ग्रामीण उद्योग और बुनियादी ढांचे के लिए क्षेत्र विशेष के अनुकूल वित्तीय समाधान विकसित करने को कहा। राज्यपाल ने महाराष्ट्र में स्टार्टअप और वित्तीय संस्थाओं के बीच भागीदारी की बड़ी संभावना

बनाई। उन्होंने कहा कि सीड कैपिटल, ग्रोथ कैपिटल, वॉर्किंग कैपिटल, वेंचर डेट और क्रेडिट गारंटी जैसी सुविधाओं के जरूरत स्टार्टअप्स को मजबूत किया जा सकता है। यदि उद्योग, विश्वविद्यालय, इनक्यूबेटर, सरकार और वित्तीय संस्थाएं मिलकर काम करें तो नई कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी उद्यमों में बदला जा सकता है। मुंबई की भूमिका पर उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक राजधानी होने के कारण यहां प्रमुख बैंक, वित्तीय संस्थाएं, शेयर बाजार, बीमा कंपनियां और पूंजी बाजार से जुड़े संगठन मौजूद हैं। महाप्राष्ट्र की औद्योगिक, शहरी, आईटी, अक्षय ऊर्जा और बुनियादी ढांचा क्षमता वित्तीय संस्थाओं के लिए बड़े अवसर प्रस्तुत करती है। राज्यपाल ने डिजिटल बैंकिंग और तकनीक के बढ़ते उपयोग के साथ साथवर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और ग्राहक संरक्षण को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग से ग्राहकों से सेवा और इस क मूल्यंकन बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इनके लिए सुरक्षित सिस्टम, पारदर्शी प्रक्रियाएं और प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था जरूरी है।

जुहू में अजय देवगन के बंगले पर BMC की कार्रवाई

संवाददाता
मुंबई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) में जुहू स्थित अभिनेता अजय देवगन से जुड़े एक बंगले में किए गए कथित अश्लील निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुछ हिस्सों को तोड़ देया है। यह संपत्ति अपोलो को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी परिसर में स्थित बताई गई है। जानकारी के अनुसार, बंगला 'फ्लोरल मैलून प्राइवेट लिमिटेड' नामक कंपनी को दीर्घ पर दिया गया था। बीएमसी का कहना है कि परिसर के भीतर आवश्यक मंजूरी के बिना पार्टिशन, खिड़कियां और अन्य संरचनात्मक बदलाव किए गए थे। बीएमसी ने इस संबंध में 10 सितंबर को संबंधित न्याय को नोटिस जारी कर काम रोकने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। निर्धारित समय में संतोषजनक दस्तावेज नहीं मिलने और कथित निर्माण जारी रहने के बाद बीएमसी ने 12 अक्टूबर को कार्रवाई कर अनधिकृत हिस्सों को तोड़ दिया। महानगर पालिका का कार्रवाई की पुष्टि की है। हालांकि, इस मामले में अभिनेता अजय देवगन या संबंधित कंपनी और से कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने आने की जानकारी नहीं है। बीएमसी अब यह जांच कर रही है कि संपत्ति में किए गए सभी बदलाव स्वीकृत नक्शे और भवन नियमों के अनुरूप थे या नहीं। आगे की कार्रवाई दस्तावेजों और संबंधित अनुमतियों की जांच के आधार पर तय की जाएगी।

सोने की चेन के लिए 17 वर्षीय दोस्त की हत्या ठाणे में पकड़े गए दो नाबालिग

संवाददाता
ठाणे। कासरवडवली पुलिस ने ठाणे इशिम के आजाद नगर निवासी 17 वर्षीय लड़के की हत्या की गुन्थी सुलझाने का दावा किया है। मामले में उसके दो नाबालिग दोस्तों को पकड़ा गया है। पुलिस के अनुसार, दोनों ने कथित तौर पर उनकी सोने की चेन लूटने के लिए हत्या की साजिश रची थी। पीड़ित 24 सितंबर की शाम करीब 7 बजे घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिवार ने अगले दिन कासरवडवली पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। शुरुआत में भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत अपहरण का मामला दर्ज किया गया था।

गंज के दौरान पीड़ित के एक सहाया और करीबी दोस्त ने पुलिस को बताया कि उसने 24 सितंबर की रात करीब 8:15 बजे पीड़ित को सफेद होंडा एक्टिवा पर एक अज्ञात युवक के साथ घोड़बंदर रोड की ओर जाते देखा था। पुलिस ने इस सूचना के आधार पर ब्रम्हंड सर्कल और आसपास लगे करीब 80 से 90 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, लेकिन इस दावे की पुष्टि नहीं हुई। इसके बाद पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सेल टावर लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया। पुलिस के अनुसार, पृथताछ में सहाया के बयान और तकनीकी साक्ष्यों में विरोधाभास सामने आई। 15 अक्टूबर को दोबारा पृथताछ के दौरान उसने कथित

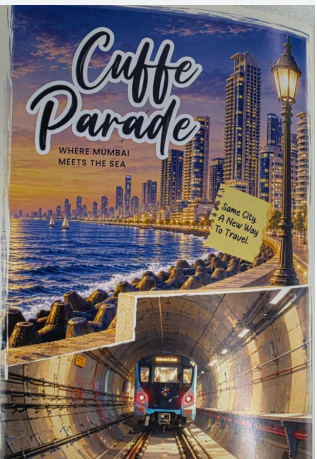
जन्मदिन पार्टी और बाइक के लिए पैसों की जरूरत बनी वजह, शव जलाकर और मोबाइल बस में फेंककर सबूत मिटाने की कोशिश का आरोप



पर अपराध में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली और दूसरे नाबालिग साथी का नाम भी बताया। पुलिस जांच के अनुसार, दोनों नाबालिग पीड़ित के दसवीं कक्षा के सहपाठी रहे थे। आरोप है कि एक दिन जन्मदिन की पार्टी के लिए पैसे चाहिए थे, जबकि दूसरा मोटरसाइकिल खरीदना चाहता था। इसी कारण दोनों ने पीड़ित की पैसे की चेन लूटने की योजना बनाई। 24 सितंबर की रात करीब 8:30 से 9 बजे के बीच दोनों ने पीड़ित को सिगरेट पीने के लक्ष्ये ब्रह्मांड फेज-2 के पास सुनसान गली वाड़ा वहां इलाके में बुलाया। वहां उस कथित तौर पर चाकू से कई बार किए गए और बाद में भारी पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस का आरोप कि अगले दिन दोनों फिर घटनास्थल पर पहुंचे और पहचान व सबूत मिटाने के लक्ष्ये शिव पर पेट्रोल डालकर आग लगा कर सार्वजनिक बस में फेंक दिया गया,

पुलिस की जांच भटकाई जा सके।
मैने नाबालिगों से मिली जानकारी के बाद
पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने घने
झाड़ी वाले इलाके की तलाशी ली, जहां
पर पीएम के आश्रिक रूप से जले अवशेष
प्राप्त कर लिए गए। मौके से भौतिक साक्ष्य
न्युट्राने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया
गया। अब मामले में भारतीय न्याय संहिता
की धारा 103(1) और 238 के तहत
दण्डित्य। सूचित मिटाने से संबंधित धाराएं
जोड़ी गई हैं। चूँकि दोनों आरोपी नाबालिग
हैं, इसलिए उनके खिलाफ आगे की कानूनी
क्रिया कियो न्याय कानून के तहत
की जाएगी। पूरी कार्यवाई पुलिस आयुक्त
आशुतोष दुंबर, संयुक्त पुलिस आयुक्त डॉ.
मनोहर चह्दान, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त
प्रशोक दुधे, डीसीपी प्रसात कदन और
एसीपी ममता डिसूजा के मार्गदर्शन में
है। जांच टीम का नेतृत्व वरिष्ठ पुलिस
निरीक्षक निवृत्ति कोल्हटकर और सहायक
पुलिस निरीक्षक अमोल कोलेकर ने किया।

मुंबई मेट्रो-3 के यात्रियों के लिए देश का पहला 'मेट्रो पासपोर्ट' लॉन्च, 10 स्टेशनों पर बिक्री शुरू



संवाददाता
मुंबई। मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एएमएमआरसी) ने एक्वा लाइन (मेट्रो-3) के यात्रियों के लिए देश के पहले मेट्रो पासपोर्टों और स्टेशन स्टैम्प ट्रेल की बेवकूफ शुरु कर दी है। शुक्रवार से शुरू की गई इस अनूठी पहल के तहत यात्री अब मेट्रो यात्रा के दौरान विभिन्न स्टेशनों की विशेष मुहरें एकत्र कर सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य मुंबईवासियों और पर्यटकों के लिए मेट्रो यात्रा को अधिक आकर्षक और यादगार बनाना है। एएमएमआरसी के अनुसार, विशेष 'एक्वा लाइन पासपोर्ट' को मेट्रो-3 के पूर्ण संचालन की पहली वर्षगांठ के अवसर पर पेश किया गया है। सीमित संस्करण में उपलब्ध इस पासपोर्ट की कीमत 250 रुपये निर्धारित की गई है। इसे केवल डिजिटल भुगतान के माध्यम से खरीदा जा सकेगा। यह पासपोर्ट कफर, रैक, चर्चगेट, हुतात्मा चौक, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी), चण्डी, वल्ली, सिड्ढिविनायक, धारावी, बांद्रा-वेल्लोरी कॉम्प्लेक्स (बीकेसी), छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, टर्मिनल-2 (सीएसएमआईए-टी2) और मरोठ नाका सहित कुल 10 मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध कराया गया है। एएमएमआरसी ने बताया कि पासपोर्ट की बेवकूफ 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर की जाएगी। इसमें पोस्टकार्ड की शैली में आकर्षक कलाकृतियाँ और विभिन्न मेट्रो स्टेशनों की मुहरें संग्रह करने के लिए अलग गुच्छ दिए गए हैं। यात्री एक्वा लाइन के अलग-अलग स्टेशनों पर जाकर निर्धारित स्थानों से विशेष स्टैम्प प्राप्त कर सकेंगे। इस तरह उनका मेट्रो पासपोर्ट मुंबई की भूमिगत मेट्रो यात्रा की यादों का संग्रह बन सकेगा। एएमएमआरसी के मुताबिक, इस पहल के माध्यम मुंबई की एक्वा लाइन देश की पहली स्वतंत्र मेट्रो सेवा बन गई है, जिसका अपना अद्वितीय मेट्रो पासपोर्ट और स्टेशन आभाषित स्टैम्प ट्रेल है। मेट्रो प्रशासन का मानना है कि इस पहल से यात्रियों, विशेषकर युवाओं, परिवारों और पर्यटकों को मुंबई मेट्रो-3 के विभिन्न स्टेशनों से जुड़ने का नया अनुभव मिलेगा। साथ ही मेट्रो यात्रा को केवल परिवहन के साधन तक सीमित न रखकर एक यादगार अनुभव बनाने में मदद मिलेगी।

महाराष्ट्र शासन
कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई (सा. बां.) विभाग,
प्रशासकीय इमारत, १ ला मजला,
भवनस कॉलेज जवळ, दादाभाई रोड, अंधेरी (प.), मुंबई- ४०००५८.
E-mail-northmumbai.ce@mahapwd.com
दुरध्वनी क्रमांक .०२२-२६२३१९४४ फॅक्स - २६२०५७८८
ई-निविदा सूचना क्र. १९ सन २०२६-२७ (तिसरी वेळ)

महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई (सा.बां.) विभाग, मुंबई (दुरध्वनी/फॅक्स क्रमांक-२६२३१९४४/२६२०५७८८) हे मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग मुंबई यांच्या मान्यता प्राप्त तालिकेवरील यादी मध्ये समाविष्ट असल्याचा अनुभवही वास्तुशास्त्रज्ञान कट्टन खालील कामाकरीता ई- देकार मागवित आहेत. विभागा कागदपत्र शासनाच्या संकेतस्थळावर <https://mahatenders.gov.in> व www.mahapwd.com येथे उपलब्ध असतील. तसेच देकार निविदा स्विकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार अधीक्षक अभियंता, मुंबई (सा.बां.) मंडळ, फोर्ट, मुंबई तसेच कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई (सा.बां.) विभाग, अंधेरी (प.), मुंबई यांनी राखून ठेवला आहे. अट असलेली निविदा स्विकारली जाणार नाही.

अ.क्र.	कामाचेवर्ग	अंदाजित रक्कम
१	सार्वजनिक बांधकाम विभागाकरीता बांद्रा (पूर्व) मुंबई येथील शासकीय वसाहतीत कार्यालयाचे बांधकाम करणे. (प्रकल्पाचे कामाकरीता वास्तुशास्त्रीय संकल्पना व आराखडे, आर.सी.सी. संकल्पन, MEP Design आणि प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार सेवांकरीता खाजगी सल्लागार नेमणूक करणे बाबत	रु.४६,५४,३४२/-

टिप: वॉलर "ई" निविदा सूचना <https://mahatenders.gov.in> व www.mahapwd.com येथे पहावयास तसेच डाऊनलोड करावयास मिळेल. सदर निविदेसूचनेमध्ये काही बदल होत असल्यास या वेबसाईटवर कळविण्यात येईल.

१	ई-निविदा उपलब्ध कालावधी- दि.	१५/१०/२०२६, दुपारी १५.०० ते दि. २१/१०/२०२६ दुपारी १५.०० पर्यंत
२	ई-निविदा उघडणी- दि.	२२/१०/२०२६ दुपारी १५.०० वाजता

कार्यकारी अभियंता,
 उत्तर मुंबई (सा.बां.) विभाग,
 अंधेरी, मुंबई.

जा.क्र.काअ/उमुवि/निविदा/६९० तिर्जाक :-

14 OCT 2026

डीजीआईपीआर: आरअसी 2026-27/क्र 5/सी 3263

अवैध एग-डोनेशन रैकेट मामले में ED की महाराष्ट्र में 11 ठिकानों पर छापेमारी

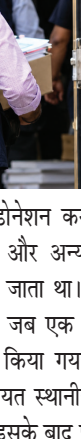
संवाददाता
मुंबई। प्रवर्तन निदेशावली (ED) ने कथित अवैध मानव अंडाणु निकालने और बेचने के रैकेट से जुड़े मनी ट्रेल की जांच के बदल चुकवा कर महाराष्ट्र के बदलपुर, उल्हासनगर, नासिक और बारामती समेत 1 ठिकानों पर तलाशी ली। कार्रवाई में कर्जिलिटी सेंटर, अस्पताल, गिरफ्तार एजेंटों और अन्य आरोपियों से जुड़े परिसरों को शामिल किया गया। ED इस कथित नेटवर्क से जुड़े वित्तीय लेनदेन, बिचौलियों के भूमिका और उन महिलाओं के जांच कर रही है, जहां महिलाओं को कथित तौर पर बार-बार एग-रिट्रीवल प्रक्रिया से गुजरने के लिए भेजा जाता था। जांच एजेंसी को संदेह है कि 40 से अधिक आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं का इस नेटवर्क में स्तेमाल किया गया। उल्हासनगर में ED ने कैप-4 के सुभाष टेकड़ी स्थित दाहे से जुड़े परिसरों की तलाशी ली। एजेंसी के अनुसार, वह कथित तौर पर महिलाओं को इस प्रक्रिया के लिए लाने, स्थानीय स्तर पर उनके आवागमन की व्यवस्था करने और विना उचित चिकित्सीय प्रिस्क्रिप्शन सोनोग्राफी कराने में भूमिका निभाती थी। एक अन्य गिरफ्तार एजेंट अश्विनी रुपेश शबकुस्वार से जुड़े ठिकानों पर भी तलाशी ली गई। उल्हासनगर के एक सोनोग्राफी केंद्र भी भी जांच की गई, जिसे स्थानीय निकाय मार्च 2026 में कथित निगम उल्लंघन के बाद सील किया था। बदलपुर में एक कथित अनधिकृत IVF सुविधा और नासिक में एक IVF सेंटर तथा उसके निदेशक से जुड़े परिसरों की भी तलाशी ली गई।

प्रति चक्र 25 से 30 हजार रुपये देने का आरोप

पह कार्रवाई बदलापुर पुलिस की जांच के बाद शुरू हुई। पुलिस ने मई 2026 में लिखिल चार्जशीट में आरोप लगाया था कि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को पैसे का लालच देकर बार-बार एग-डोनेशन प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार किया जाता था। कथित तौर पर प्रत्येक चक्र के लिए 25 हजार से 30 हजार रुपये दिए जाते थे। पुलिस जांच के अनुसार, महिलाओं को 10 से 12 दिनों तक हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते थे, ताकि अंडाणु उत्पादन बढ़ाया जा सके। इसके पहले और बाद में सोनोग्राफी कराई जाती थी और रिपोर्ट अलग-अलग राज्यों के IVF तथा ART सेंटर्स को भेजी जाती थी। अंडाणु तैयार होने पर महिलाओं को कथित तौर पर इन केंद्रों में ले जाकर ऑपरेशन थिएटर में एग-रिट्रीवल कराया जाता था। एक मामले में एक महिला के लिखित रूप से 33 बार ऐसी प्रक्रिया से गुजरने की बात सामने आई है।

फर्जी आधार और दस्तावेजों के इस्तेमाल की भी जांच

पुलिस ने यह भी आरोप लगाया है कि महिलाओं की पहचान छिपाने और बार-बार



ग-डोनेशन कराने के लिए फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जाता था। मामला उस समय सामने आया जब एक महिला ने कथित तौर पर दावा किया गया भुगतान नहीं मिलने की शिकायत स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों से की। इसके बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बदलापुर में सुलक्षणा गाडेकर (44) के घर पर छापा मारा। वहां से करीब 3.94 लाख रुपये मूल्य के हार्मोन इन्जेक्शन और सिरिज बरामद होने का दावा किया गया। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में गाडेकर ने कथित तौर पर महिलाओं को प्रेरित करने, सोनोग्राफी की व्यवस्था करने, हार्मोनल इन्जेक्शन लगाने और IVF सेंटरों में रिपोर्ट भेजने की भूमिका स्वीकार की थी।

5,000 पन्नों की चार्जशीट, 15 आरोपी

बदलापुर पुलिस ने मई 2026 में गौहट्टासनगर की अदालत में करीब 5,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें गांच डॉक्टरों समेत 15 आरोपियों के नाम शामिल थे और आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने 25 आरोपों के बयान दर्ज किए और करीब 250 ग-डोनेशन प्रक्रियाओं की जांच की।

कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में महाराष्ट्र साइबर सेल के सामने पेश हुए हनी सिंह

संवाददाता मुंबई। फैपर और म्यूजिक प्रोड्यूसर यो यो हनी सिंह, जिनका असली नाम हिरदेश सिंह है, शुक्रवार 16 अक्टूबर को महाराष्ट्र साइबर सेल के सामने पेश हुए। जांच अधिकारियों ने उनसे एक कॉन्सर्ट के दौरान की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पूछताछ की। करीब दो घंटे तक उनका बयान दर्ज किया गया, जिसके बाद वह कड़ी सुरक्षा के बीच वहां से रवाना हो गए। बताया गया है कि हनी सिंह ने पूछताछ के लिए 22 अक्टूबर को पेश होने की अनुमति मांगी थी, लेकिन जांच एजेंसी ने उनकी मांग स्वीकार नहीं की और तय तारीख पर ही उपस्थित होने को कहा। इसके बाद वह 16 अक्टूबर को साइबर सेल कार्यालय पहुंचे। महाराष्ट्र साइबर सेल के सूत्रों के मुताबिक, हनी सिंह को इस मामले में कई बार समन भेजे गए थे, लेकिन वह पहले तय तारीखों पर पेश नहीं हो सके। उन्होंने विदेश में होने का हवाला देते हुए अतिरिक्त समय मांगा था। इससे पहले उन्हें 5 अक्टूबर को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह उस दिन उपस्थित नहीं हुए। सितंबर में जारी नोटिस में उन्हें मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थित महाराष्ट्र साइबर सेल कार्यालय में पेश होने के निर्देश दिए गए थे। एजेंसी ने इसे अंतिम रिमाइंडर बताया था। अब 16 अक्टूबर को पेश होने के बाद उनका

करीब दो घंटे तक दर्ज हुआ बयान, कॉन्सर्ट में कही बात को लेकर चल रही जांच



बयान दर्ज कर लिया गया है।

जनवरी के कॉन्सर्ट से जुड़ा है मामला

मामला जनवरी 2026 में दिल्ली में आयोजित रैपस नानकू और करुण के एक कॉन्सर्ट से जुड़ा है, जिसमें हनी सिंह भी शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने दिल्ली की ठंड का जिक्र करते हुए गाड़ी में इंटीमेट होने से संबंधित कथित टिप्पणी की थी। इसी दौरान उन्होंने कंडोम के इस्तेमाल और सुरक्षित यौन संबंधों की बात भी कही थी। कॉन्सर्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुंबई के एक शिकायतकर्ता ने महाराष्ट्र साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। इसी शिकायत के आधार पर जांच शुरू की गई और हनी सिंह को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया।

हनी सिंह ने पहले दी थी सफाई

विवाद बढ़ने के बाद हनी सिंह ने वीडियो जारी कर अपनी टिप्पणी पर सफाई दी थी। उनका कहना था कि उनका उद्देश्य युवाओं को सुरक्षित यौन संबंधों और कंडोम के इस्तेमाल के प्रति जागरूक करना था। उन्होंने यह भी कहा था कि कुछ दिन पहले उनकी मुलाकात स्त्री रोग विशेषज्ञों और सेक्सोलॉजिस्ट से हुई थी, जहां युवाओं में असुरक्षित यौन संबंधों के कारण फैलने वाले संक्रमणों को लेकर चर्चा हुई थी। हनी सिंह ने स्वीकार किया था कि अपनी बात रखने के लिए इस्तेमाल की गई भाषा के बाद मुंबई के एक शिकायतकर्ता ने महाराष्ट्र साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। इसी शिकायत के आधार पर जांच शुरू की गई और हनी सिंह को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया।

‘बारह साल, बारह सवाल’: बैंकिंग व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा को घेरा

संवाददाता लखनऊ, उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बैंकिंग व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर ‘बारह साल, बारह सवाल’ शीर्षक से 12 सवाल उठाए हैं। उन्होंने बैंकों की मजबूती के दावों के बीच बैंक बिक्री, खातों से कटौती, केवाईसी, साइबर उगी, कर्ज और कर्मचारियों की स्थिति जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा है। अखिलेश यादव ने सवाल किया कि यदि बैंक मजबूत हुए हैं तो उन्हें बेचा क्यों जा रहा है और गरीब लोगों के खातों से पैसे क्यों काटे जा रहे हैं। उन्होंने केवाईसी के नाम पर ग्राहकों को होने वाली परेशानी और बैंकों से बड़ी रकम का कर्ज लेकर विदेश भागे लोगों को वापस लाकर कार्रवाई करने में हो रही देरी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में बैंक शाखाएं और एटीएम बंद होने से लोगों को नकदी के लिए होने वाली परेशानी का जिक्र किया। साथ ही किसानों, छात्रों और छोटे दुकानदारों को बिना बिचौलिये और गारंटर के आसानी से कर्ज नहीं

बैंक बिक्री, खातों से कटौती, साइबर ठगी, महंगे कर्ज और ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं बंद होने जैसे मुद्दे उठाए



मिलने पर भी सवाल किया।

साइबर ठगी और महंगे कर्ज का मुद्दा सपा प्रमुख ने साइबर ठगी का शिकार हुए लोगों को रकम वापस मिलने में देरी और बैंक तथा थातों के चक्कर लगाने की समस्या उठाई। उन्होंने होम लोन और शिक्षा ऋण की ब्याज दरों, डिजिटल ट्रांजेक्शन फेल होने के बाद रकम कई दिनों तक अटक रही और CIBIL स्कोर में छोट्टी चूक से युवाओं को कर्ज मिलने में दिक्कतों पर भी सवाल किए। अखिलेश यादव ने बुजुर्गों और कम पढ़े-लिखे लोगों को UPI तथा

ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए प्रत्येक बैंक शाखा में सहायता काउंटर की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने बैंक कर्मचारियों की मांगें, नई भर्तियों की कमी और मौजूदा कर्मचारियों पर बढ़ते काम के दबाव को भी अपने सवालों में शामिल किया। अखिलेश यादव की पोस्ट का केंद्र बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता, ग्राहक सुरक्षा, कर्ज की रहने और CIBIL स्कोर में छोट्टी चूक से युवाओं को कर्ज मिलने में दिक्कतों पर भी सवाल किए। अखिलेश यादव ने बुजुर्गों और कम पढ़े-लिखे लोगों को UPI तथा

गाजियाबाद में सीएम योगी का सपा पर तीखा हमला बोले— पहले दंगे और कर्फ्यू थे, अब विकास और सुरक्षा की पहचान

संवाददाता गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गाजियाबाद के डासना स्थित सुंदरदीप कॉलेज में आयोजित शिक्षक-स्नातक सम्मेलन में समाजवादी पार्टी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। विधान परिषद चुनाव के मतदाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सपा सरकार के कार्यक्रमों में दंगों, कर्फ्यू, खराब सड़कों और निवेश की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की पहचान सुरक्षा, बेहतर बुनियादी ढांचे, धार्मिक आयोजनों और शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों से बन रही है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत भगवान राम, हनुमान, वृंदावन के बांके बिहारी, मां शाकुंभरी और भगवान शिव का स्मरण करते हुए की। उन्होंने नवरात्र के अवसर पर मां कात्यायनी की आराधना का उल्लेख किया और प्रदेश की सांस्कृतिक एवं धार्मिक परंपराओं पर प्रकाश डाला।

सपा के पीडीए पर साधा निशाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी विधान परिषद चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की रणनीति पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा ने राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार अपना रुख बदला है और टिकट वितरण में परिवारवाद तथा बाहरी प्रभाव को प्राथमिकता दी है। सपा के

रामलीला और कांवड़ यात्रा का किया उल्लेख

मुख्यमंत्री ने कहा कि गाजियाबाद में बड़े स्तर पर रामलीला के आयोजन हो रहे हैं और प्रदेश में धार्मिक कार्यक्रमों के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध है। उन्होंने दावा किया कि पूर्ववर्ती सपा सरकार के समय कांवड़ यात्रा, रामलीला और दुर्गापूजा जैसे आयोजनों में अनेक कठिनाइयाँ आती थीं। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम के विकास और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर विशेष ध्यान दे रही है। सहारनपुर में

मां शाकुंभरी कॉरिडोर परियोजना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एलिवेटेड मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है। इससे बरसात के दौरान आने वाली परेशानियों को कम करने में मदद मिलेगी।

नमो भारत ट्रेन, जेवर एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं का जिक्र

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि दिल्ली और मेरठ के बीच नमो भारत ट्रेन ने आवागमन को सुगम बनाया है। उन्होंने जेवर एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सपा सरकार ने एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए धनराशि रोकने का काम किया था, जबकि भाजपा सरकार ने इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर और अलीगढ़ में विश्वविद्यालयों के विकास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज की सुविधा उपलब्ध कराने का दिशा में सरकार काम कर रही है।

नौकरियों और स्टार्टअप को लेकर सरकार की उपलब्धियाँ गिनाई

स्पाइन सर्जरी के बाद अस्पताल से घर लौटीं नुसरत भरुचा

बाली में हादसे के बाद हुई थी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी टीम ने कहा— रिकवरी में लगेगा समय

संवाददाता मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरुचा की सेहत को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। बाली में हुए एक हादसे के बाद उनकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी सफल रही और अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अभिनेत्री की टीम ने सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी साझा की है। टीम के अनुसार, हादसे के बाद नुसरत को मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा और बाद में उनकी स्पाइन सर्जरी की गई। सर्जरी सफल रहने के बाद अब वह घर लौट आई हैं और अपने करीबियों के बीच रहकर रिकवरी पर ध्यान दे रही हैं। हालांकि टीम ने साफ किया है कि नुसरत को पूरी तरह स्वस्थ होने में अभी समय लगेगा।

फिलहाल उनका ध्यान आराम करने, ताकत वापस पाने और डॉक्टरों की सलाह के अनुसार धीरे-धीरे सामान्य दिनचर्या में लौटने पर है। जानकारी के मुताबिक, नुसरत अक्टूबर की शुरुआत में काम और छुट्टियों के सिलसिले में बाली गई थीं। वहीं करीब 1 अक्टूबर को उनके साथ हादसा हुआ। घटना के बाद उन्हें बाली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में एयर एंबुलेंस के जरिए मुंबई लाया गया, जहां आगे की जांच और सर्जरी की गई। नुसरत ने अपनी



रिकवरी से जुड़ी कुछ झलकियां सोशल मीडिया पर भी साझा की थीं। एक पोस्ट में उन्होंने रिक्लाईनिंग व्हीलचेयर और सूर्यास्त की तस्वीर के साथ लिखा था, 'पिकचर अभी बाकी है मेरे दोस्त।' एक अन्य पोस्ट में उन्होंने अपनी स्थिति को लेकर संकेत दिया कि वह धीरे-धीरे ठीक हो रही हैं और सकारात्मक बनी हुई हैं। अभिनेत्री की टीम ने इस मुश्किल समय में प्रशंसकों और शुभचिंतकों की ओर से मिले प्यार, दुआओं और शुभकामनाओं के लिए आभार जताया है। फिलहाल नुसरत भरुचा घर पर आराम कर रही हैं। उनकी टीम ने पूरी तरह स्वस्थ होने की कोई निश्चित समयसीमा नहीं बताई है।

कारोबारी शिवा शर्मा की मौत मामले में मॉडल श्रद्धा शर्मा समेत तीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट की तैयारी

संवाददाता लखनऊ, उत्तर प्रदेश। हजरतगंज के कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में पुलिस ने मॉडल श्रद्धा शर्मा, उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर आदिल उर्फ दानिश के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कराने के लिए अदालत में अर्जी दी है। पुलिस का दावा है कि मामले में आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाए जा चुके हैं और जल्द वारंट जारी हो सकता है। जांच एजेंसियों को श्रद्धा की आखिरी लोकेशन नेपाल के दांग जिले के भालुवांग इलाके में मिली है। बताया जा रहा है कि वह अपनी बहन रश्मि और दो युवकों के साथ नेपालगंज से आगे बढ़ते हुए भालुवांग तक पहुंची थी।

गुरुवार को यह लोकेशन मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां नेपाल पुलिस के संपर्क में रहकर उसकी गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि भालुवांग के बाद श्रद्धा और उसके साथ मौजूद लोगों की लोकेशन स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस विभिन्न संभावित रास्तों और सीमावर्ती क्षेत्रों की जानकारी जुटा रही है। जांच में यह बात भी सामने आई है कि श्रद्धा से जुड़ी एक गाड़ी 18 अक्टूबर 2025 को बहराइच पहुंची थी। नानपारा के पास चीनी मिल के निकट स्थित टोल प्लाजा पर वाहन का टोल टैक्स कटने का रिकॉर्ड मिला है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी के अनुसार,



स्थानीय पुलिस लखनऊ पुलिस की जांच टीम को सहयोग कर रही है और मामले से जुड़े हर बिंदु की पड़ताल की जा रही है। इस बीच श्रद्धा द्वारा कथित तौर पर बनाया गया शिवा का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में श्रद्धा, शिवा पर जैलरी चोरी करने का आरोप लगाती दिखाई देती है। वीडियो में शिवा कथित तौर पर तीन सोने की चेन और एक ब्रेसलेट बेचने की बात स्वीकार करते हुए करीब छह लाख रुपये की रकम एक महिने में लौटाने की बात कह रहा है। वह अपनी कार गिरवी रखने की पेशकश भी करता सुनाई देता है। पुलिस ने इस वायरल वीडियो को भी जांच में शामिल किया है और इसकी प्रामाणिकता तथा पूरे घटनाक्रम से उसके संबंध की पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद ही शिवा शर्मा की मौत से जुड़े सभी पहलुओं पर स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।



मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने सरकारी नियुक्तियों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि पिछले नौ वर्षों में लगभग साढ़े नौ लाख नौकरियां देने की दिशा में काम किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के युवा अब केवल नौकरी पाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उद्यमिता और स्टार्टअप के माध्यम से दूसरों को रोजगार देने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश में लगभग 24 हजार स्टार्टअप हैं। उन्होंने मेट्रो और अन्य परिवहन परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार शहरी यातायात सुविधाओं के विस्तार पर भी काम कर रही है।

शिक्षकों को बताया युग निर्माता शिक्षक-स्नातक सम्मेलन में मुख्यमंत्री

पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचीं कृति सेनन

नाम, चेहरा, आवाज और तस्वीरों के बिना अनुमति इस्तेमाल पर रोक की मांग, अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को



संवाददाता मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपनी पहचान से जुड़े नाम, चेहरा, आवाज, तस्वीर और वीडियो जैसी सामग्री का बिना अनुमति व्यावसायिक या अन्य गलत इस्तेमाल रोकने की मांग की है।

शुक्रवार, 16 अक्टूबर को मामले की सुनवाई जस्टिस पुरुषोत्तम कुमार कौरव की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि मौजूदा कानून के तहत किसी व्यक्ति की पहचान को किस सीमा तक कानूनी संरक्षण दिया जा सकता है। कृति सेनन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण आनंद को अदालत ने पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़े पुराने न्यायिक फैसलों, शोध सामग्री और संबंधित कानूनी सिद्धांतों की सूची पेश करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि

ऐसे मामलों की सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिवीजन (IPD) का अधिकार क्षेत्र किस सीमा तक लागू होता है। कृति की ओर से अदालत को बताया गया कि पर्सनैलिटी राइट्स में किसी व्यक्ति का नाम, आवाज, तस्वीर, वीडियो और अन्य पहचान योग्य विशेषताएं शामिल हो सकती हैं। किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी पहचान का व्यावसायिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना भी इस विवाद का अहम हिस्सा है। अदालत ने कृति सेनन के वकील से इस विषय से जुड़े पुराने फैसले, रिसर्च पेपर और विस्तृत कानूनी पक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। वकील ने बताया कि आवश्यक दस्तावेज दाखिल किए जाएंगे और अदालत के अधिकार क्षेत्र को लेकर कोई बाधा नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। कोर्ट संबंधित दस्तावेजों और कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद आगे का आदेश जारी करेगा।

ब्लैक-व्हाइट गाउन में अशनूर कौर का ग्लैमरस अंदाज, नाइट फोटोशूट ने खींचा सबका ध्यान

संवाददाता मुंबई। टीवी और डिजिटल दुनिया की चर्चित अभिनेत्री अशनूर कौर एक बार फिर अपने स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में सामने आई उनकी तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर फैस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन वाले आकर्षक गाउन में अशनूर बेहद खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरपूर नजर आ रही हैं। अशनूर ने इस फोटोशूट में ब्लैक और व्हाइट रंग का फिगर-हर्गिंग गाउन पहना है, जो उनके लुक को क्लासी और मॉडर्न टच दे रहा है। गाउन का डिजाइन सादा होने के बावजूद काफी प्रभावशाली दिखाई देता है।

उनके पूरे लुक में सादगी और स्टाइल का शानदार संतुलन नजर आता है। तस्वीर में एक ओर अशनूर कैमरे की तरफ देखते हुए पोज दे रही हैं, वहीं दूसरी ओर एक फोटो में वह शहर के खूबसूरत नाइट व्यू को निहारती दिखाई देती हैं। इन दोनों तस्वीरों को साथ देखने पर एक बेहतरीन विजुअल स्टोरी का अहसास होता है, जो दर्शकों को काफी आकर्षित कर रही है। इस फोटोशूट की सबसे खास बात उसका बैकग्राउंड है। ऊंची इमारत से दिखाई देती शहर की चमकती रोशनियां तस्वीरों को और भी खास बना रही हैं। अशनूर का ग्लैमरस अंदाज और रात का मनमोहक नजारा मिलकर तस्वीरों में एक सिनेमाई एहसास पैदा कर रहे हैं। बालकनी में खड़े होकर शहर को निहारती अशनूर को तस्वीर फैस को खास तौर पर पसंद आ रही है। यह फोटो आत्मविश्वास, सुकून और आधुनिक जीवनशैली को बेहद प्रस्तुत करती है। अपने इस लुक को अशनूर ने मिनिमल मेकअप और सॉफ्ट हेयरस्टाइल के साथ पूरा किया है। खुने बाल, हल्का मेकअप और कम ज्वेलरी ने उनकी प्राकृतिक



खूबसूरती को और निखार दिया है। यही वजह है कि पूरा फोकस उनके आउटफिट और व्यक्तित्व पर बना रहता है। फैशन एक्सपर्ट्स की मानें तो इन दिनों मिनिमलिस्ट स्टाइल काफी ट्रेंड में है, और अशनूर कौर ने इस ट्रेंड को बेहद खूबसूरती से कैरी किया है। उनका यह लेटेस्ट लुक न केवल फैशन प्रेमियों को पसंद आ रहा है, बल्कि युवाओं के बीच भी स्टाइल इन्सपिरेशन बनता दिखाई दे रहा है।